आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोग तीसरे दिन भी नैशनल हाइवे 21 पर डटे रहे। मंगलवार की देर शाम वार्ता का दौर शुरु हुआ।

आरक्षण के लिए सैनी समाज के लोग तीसरे दिन भी भरतपुर हाईवे पर डटे रहे

नैशनल हाईवे 21 पर पिछले तीन दिनों से यातायात पूरी तरह से ठप्प पड़ा है

भरतपुर, 14 जून (निसं)। माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज के लोग सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के अरौदा गांव में पिछले तीन दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे इस राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप्प है।

मंगलवार की देरशाम को आंदोलनकारियों से वार्ता का दौर शुरू हुआ है। शाम को सैनी समाज एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आईजी ऑफिस पहुंचा। यहां संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, कलैक्टर आलोक रंजन, आईजी प्रसन्न खमेसरा और एसपी श्याम सिंह के साथ शुरुआती वार्ता चली। इस आंदोलन में रास्ता जाम करने आम लोगों को परेशानी में डालने, यातायात अवरूद्ध करने के संबंध में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने की भी चर्चा है।

दूसरी तरफ संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा ने भरतपुर के चार कस्बों नदबई, वैर, भुसावर और उच्चैन मिल सके और आपकी बात भी सरकार तक पहुंच सके।

राजस्थान के भरतपुर जिले में सैनी माली कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज का 12प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर

- **आरक्षण की मांग को लेकर माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज के लोग गत तीन दिनों से एन.एच. 21 पर धरने पर बैठे हैं।**
- **भरतपुर के चार कस्बों में इन्टरनैट बुधवार सुबह 11 बजे तक बंद रहेगा।**

तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद को अगले 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। अब बुधवार सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि समाज के लोग यहां आएं और वार्ता करें, ताकि हाइवे खुले और लोगों को राहत 3 दिन से आंदोलन जारी है। आन्दोलन कर रहे लोगों ने नेशनल हाईवे नम्बर 21 आगरा - जयपुर पर नदबई तहसील के अरौदा गांव के पास चक्का जाम किया हुआ है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह 2 दिन से आंदोलन कर रहे नेताओं से वार्ता करने के लिए बैठे हुए हैं । नेताओं को वार्ता के लिए न्योता भी भेजा है। आंदोलनकारियों ने वार्ता के लिये 31 सदस्यों की लिस्ट प्रशासन को भेजी है।

मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आंदोलन से आमजन परेशान हो रहा है । भीषण गर्मी पड़ रही है तापमान 45 डिग्री के बीच चल रहा है । आंदोलन स्थल पर बुजुर्ग और महिलाएं बैठी हुई हैं यदि कोई अप्रिय घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। विश्वेन्द्र सिंह ने आंदोलनकारियों से अपील की है उनके नेता वार्ता के लिए सामने आए जिससे उनकी मांग को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि "मुझे तो फिलहाल ऐसा लगता है कि इस आंदोलन का कोई नेता भी नहीं है।"

डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में लिया

डोटासरा से बोली दिल्ली पुलिस-आज के दिन आप आपातकाल ही समझें

जयपुर, 14 जून (का.प्र.)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लगातार दो दिन से हो रही ई.डी. की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह मंगलवार को भी जारी रहा। सोमवार को जहां सभी राज्यों में ईडी की कार्यवाही के खिलाफ धरने-प्रदर्शन हुए, वहीं मंगलवार को प्रदेशों के नेताओं सहित पदाधिकारी और विधायक दिल्ली की ओर कूच कर गए। राजस्थान से भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री- विधायक दिल्ली रवाना हुए, लेकिन इन सभी को पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक लिया। सभी नेताओं को शाम तक पुलिस ने अलग-अलग थानों में रोके रखा और शाम को सबको छोड़ दिया। हालांकि सोमवार रात को ही जयपुर से जाने वाले कई नेता अलग-अलग रास्तों से एआईसीसी मुख्यालय तक भी पहुंच गए।

मंगलवार सुबह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ पदाधिकारी जैसे ही हरियाणा बॉर्डर पार करके दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे तो वसंत कुंज पुलिस ने उन्हें वहीं रोक गई। जब हम दिल्ली आ रहे थे, तो हमें बॉर्डर पर रोककर यह कहा कि आपके लिए आपातकाल है। आज के दिन आप आपातकाल ही समझें। किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री नहीं करने देने के आदेश मिले हैं। पुलिस ने हमें रोककर गाड़ियों में अपने साथ ले गई और हमें वसंतकुंज थाने के पास अज्ञात जगह पुलिस पहरे में रखा गया। ऐसी निर्दयी सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रही है। इसका खात्मा जरूरी है।" उन्होंने कहा "मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि समय आ गया है कि ऐसे जुल्मियों को 2024 में सत्ता

- **राजस्थान से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री व विधायक दिल्ली रवाना हुए, जिन्हें हरियाणा बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक लिया।**
- **सभी नेताओं को अलग-अलग थानों में रखा गया और शाम को छोड़ दिया गया, सभी फिर अलग-अलग रास्तों से ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पहुंचे।**

लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि आगे नहीं जाने देने के आदेश है। यहां पर पुलिस के साथ में डोटासरा की बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और बाद में उन्हें अज्ञात जगह रखने के बाद शाम को छोड़ दिया गया। यहां से फ्री होने के बाद डोटासरा सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पहुंच गए।

डोटासरा ने कहा कि "इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। दिल्ली में राजस्थान के लोगों को आने-जाने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। वह देश देख रहा है। आज तो हद हो से हटाना है। राहुल गांधी ना डरे हैं ना घबराए हैं। सत्य हमेशा जीता है। बीजेपी और मोदी का षड्यंत्र जरूर हारेगा।"

डोटासरा के साथ जाने वाले अन्य पदाधिकारियों को भी वसंत कुंज थाना पुलिस ने रोककर कहा हम पूरी रात से हाईवे पर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बहस के दौरान जब डोटासरा ने कहा कि क्या वह निजी काम से दिल्ली नहीं जा सकते? तो पुलिस ने कहा सारे अधिकारों की बात थाने में जाकर करेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं को वसंतकुंज थाने की बिल्डिंग में ही अलग-अलग कमरों में बैठाए रखा गया। यहां थाने की बिल्डिंग टैंट लगाया हुआ था, जिसमें भी कुछ कांग्रेसियों को रखा गया था। थाने में घुसने के बाद किसी भी नेता या कार्यकर्ता को पुलिस ने देर शाम तक बाहर नहीं जाने दिया।

बताया जाता है कि यहीं पर राजस्थान के पदाधिकारियों के अलावा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, सेवादल अध्यक्ष लालजी देसाई, एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन, एआईसीसी सेक्रेट्री बीएन संदीप, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, देशराज मीणा, जसवंत गुर्जर भी थे।

सुप्रीम कोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे हैं तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के आंदोलनकारियों का पीछा करके, पुलिस उन्हें पीट रही है।

पत्र-याचिका कहती है, "सरकार द्वारा कानून के शासन तथा नागरिकां के अधिकारों के उल्लंघन के ऐसे अस्वीकार्य हनन एवं विनाश द्वारा नृशंसता का यह प्रदर्शन संविधान तथा गारंटीयुक्त मौलिक अधिकारों का मजाक उड़ाने के समान है।

पुलिस तथा विकास अधिकारियों ने मिलकर जिस तरह से यह कार्यवाही की है, उसका स्पष्ट सार यह है कि मकान गिराया जाना सामूहिक अतिरिक्त - न्यायिक दंड का एक रूप है, जिसकी उत्तरदायी राज्य सरकार की नीति है, जो गैर कानूनी है। पत्र में यह कहते हुए, कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में माइग्रैंट मज़दूरों और पैगसस केस पर स्वत: संज्ञान लिया था, आग्रह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।

पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पास 300 से अधिक सांसद हैं तो (राष्ट्रपति) चुनाव का नतीजा क्या होगा- मैं जानता हूँ। मै राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूँगा।

उसके ठीक एक साल बाद, इस समय जब उनके विपक्ष का उम्मीदवार बनने पर चर्चा जोर पकड़ रही है लेकिन चुनाव-प्रक्रिया का मंच अभी तैयार हो रहा है तथा पवार, अपनी आदत एवं उसूल के अनुरुप, स्थिति को ध्यान से देख रहे हैं तथा उसका आँकलन कर रहे हैं। एन.सी.पी. प्रमुख की व्यवहारवादी राजनीति तथा उनके सुधार-समर्थक एजेण्डा ने उन्हें संपूर्ण देश के पूरे राजनैतिक परिदृश्य के सम्मान एवं आदर का पात्र बनाया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उन्हें अपना "राजनैतिक गुरु" कहते हैं।

पवार ने अपनी सुदीर्घ राजनैतिक यात्रा में कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं। वे सबसे पहले 1967 में बारामती विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के लिये निर्वाचित हुये। वे 1978 तक राज्य सरकार में निरन्तर मंत्री बनते रहे तथा 1978 में उन्होंने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार (1978 से 1980 तक) ग्रहण किया। वे दो बार और (1983-91 तथा 1993-95) मुख्यमंत्री रहे। वे छ: बार लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं तथा कई बार केन्द्रीय मंत्री रहते हुये विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों, जिनमें रक्षा एवं कृषि भी शामिल हैं, को संभाल चुके हैं।

1999 तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहने के बाद, वे 1999 में उस समय वे पार्टी से अलग हो गये तथा पार्टी के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया, जब पार्टी ने इटली में जन्मीं सोनिया गांधी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजैक्ट किया। वे कांग्रेस से निष्कासित कर दिये गये तथा इसके बाद उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी एन.सी.पी. बना ली।

लेकिन उनके राजनैतिक व्यवहारवाद तथा उनकी चतुराई ने सदैव ही उनकी राजनीति को परिभाषित एवं रेखांकित किया है।

इसलिये, कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद भी एन.सी.पी. ने गठबंधन सरकारें बनाने के लिये सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया- पहले महाराष्ट्र में तथा उसके बाद केन्द्र में। उनका राजनैतिक व्यवहारवाद नवम्बर 2019 में उस समय एक बार पुन: खुलकर सामने आया, जब शिवसेना के साथ अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को भूलकर, उन्होंने एम.वी.ए. सरकार के गठन में मास्टरमाइन्ड की भूमिका अदा करते हुये, एन.सी.पी., कांग्रेस एवं शिवसेना का असंभावित प्रतीत होने वाला गठबंधन खड़ा कर दिया।

दूसरे दिन भी ई.डी. द्वारा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोशिश करने वाले कांग्रेस नेताओं को पकड़ा जा सके।

बड़ी संख्या में आए कांग्रेस नेता जो ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर राहुल के साथ सत्याग्रह के रूप में धरने पर बैठने के बाद उनके साथ ई.डी. के मुख्यालय पर आए थे, की पुलिस ने पिटाई की और सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उन्हें राजधानी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। कांग्रेस ने धरने में प्रण लिया था कि वह गिरफ्तारियों और उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ बनाए गए झूठे केसों की भयभीत चालबाजियों के आगे नहीं झुकेगी।

राहुल अपनी बहन एवं ए.आई.सी.सी. महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आए थे। पुलिस ने प्रियंका को छोड़ दिया क्योंकि वह अपने सिक्योरिटी कवर के साथ थीं, जबकि गिरफ्तार किए गए नेताओं में दो मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल शामिल थे।

पूर्व केन्द्रीय गृह एवं वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, जो कि पुलिस की हाथापाई में सोमवार को घायल हो गये थे, मंगलवार को विरोध स्थल पर पुन: लौट आए। हालांकि पुलिस ने सोमवार को उन पर बल प्रयोग किए जाने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून के दुरूपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। यदि ई.डी. कानून की अनुपालना करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह कानून की पालना नहीं कर रहा है। काले धन को वैध करने के केस में पी.एम.एल.ए. (प्रिवैन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट) जबरन लगाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि पी.एम.एल.ए. कानून के तहत कोई केस दर्ज करने के बाद ही जांच कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उनके सहज प्रश्न थे: "निर्धारित अपराध क्या है। इसका कोई उत्तर नहीं है। कौनसी पुलिस एजेंसी ने एफ.आई.आर. दर्ज की है? इसका भी उत्तर नहीं है। हमने एफ.आई.आर. की कॉपी मांगी। कोई उत्तर नहीं।"

चिदंबरम ने कहा कि "निर्धारित अपराध और एफ.आई.आर. के बिना पी.एम.एल.ए. के तहत ई.डी. की जांच का सवाल ही नहीं है? स्पष्ट रूप से, वे कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, और एक लोकतंत्र में हम विरोध प्रदर्शन का हक रखते हैं।"

उन्होंने कहा कि ई.डी. ने इसी प्रकार कांग्रेस के सीनियर नेता एवं ए.आई.सी.सी. कोषाध्यक्ष पवन बंसल से एसोसिएटेड जर्नल्स के चेयरमैन के रूप में और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से यंग इण्डिया लिमिटेड के एक ट्रस्टी के रूप में अप्रैल माह में पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तथापि, ई.डी. सूत्रों का कहना है कि चिदंबरम की बात गलत है क्योंकि यंग इण्डिया के विरूद्ध इन्कम टैक्स की एक जांच में दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद ही ई.डी. ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ पी.एम.एल.ए. के आपराधिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था। दिसंबर 2015 में जब कोर्ट ने यह आशंका जतायी कि ये लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे तब सोनिया और राहुल, प्रत्येक ने 50 हजार रूपए का व्यक्तिगत बॉण्ड और मुचलका देकर अपनी जमानत कराई थी।

मंगलवार को दूसरे दिन गिरफ्तार किए गए सभी कांग्रेसी नेताओं की जुबान पर "राजनीतिक प्रतिशोध" के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार जब तक अत्याचार करती रहेगी विरोध तब तक जारी रहेगा। उन्होंने केन्द्र की भाजपा सरकार को चुनौती दी कि पिछले आठ सालों में यदि किसी भाजपा समर्थित नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो तो वह बताए। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग विपक्षी पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, केन्द्रीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले तक ड्राप किए हैं।

बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रूपयों का ऋण दिया था जिससे कि वह नैशनल हैरल्ड अखबार का एक संस्थान के रूप में अस्तित्व बरकरार रख सके और इसे काले धन को वैध करने की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि "एक रूपए तक का लेनदेन नहीं किया गया है। सिर्फ एक व्यापार की पुनर्संरचना की गई और ऐतिहासिक अखबार को जीवित रखने के लिए शेयर जारी किए गए थे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के खिलाफ ई.डी. जांच पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि वह इस प्रतिशोधी राजनीति को बंद करे और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के बजाए सुशासन पर ध्यान केन्द्रित करे। दोनों मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थे।

गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं में रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, दीपेन्द्र सिंह हूडा, रनजीत रंजन, जे.बी. माथर, इमरान प्रतापगढ़ी, यूथ कांग्रेस के प्रमुख बी.बी. श्रीनिवास और नैशनल स्टूडैन्ट्स यूनियन ऑफ इण्डिया (एन.एस.यू.आई.) के प्रमुख नीरज कुन्दन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश नेताओं को विरोध "सत्याग्रह" के पहले दिन सोमवार को भी गिरफ्तार किया गया था।

बालिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा एएसआई मदनलाल सहित पुलिसकर्मी गांव पहुंचे तथा आरोपी की तलाश शुरु की।

बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाई

मालपुरा, 14 जून (निसं)। सोमवार की शाम को पचेवर थाना क्षेत्र के ईटाखोई की ओर से नगर की ओर आ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पचेवर थाना पुलिस टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो बजरी माफिया पुलिस पर हमला कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ा ले भागे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम को पचेवर थाना पुलिस को अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली। इस पर पुलिस गश्ती दल ने ईटाखोई से नगर की ओर आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को नाकाबंदी कर रोकने का प्रयास किया तो चालक पुलिस टीम को देख ट्रैक्टर से चाबी निकाल कर जंगल में भाग गया। पुलिस टीम जब ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने जाने लगी तो कुछ ही देर बाद 15-20 लोग मोटर साइकिलों पर आए और उन्होंने बीच रास्ते में पुलिस जवानों को घेर लिया, जिससे पुलिस व उनके बीच झड़प भी हुई। इस दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस जवानों से मारपीट कर ट्रैक्टर छुड़ा लिया और उनकी जेब में रूपये डालकर जबरन वीडियो बना लिया। उन्होंने वीडियो के वायरल करने की धमकी दी। जवानों ने थाने पहुंच सम्पूर्ण घटनाक्रम को थानाधिकारी रतन सिंह को अवगत करवाया। जिस पर थानाधिकारी ने राजकार्य में बाधा डालने की विभिन्न धाराओं में 15 से 20 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी।

- **अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी की, जिसे देखकर ट्रैक्टर चालक भाग निकला।**
- **बाद में जब पुलिस ट्रैक्टर को थाने ले जा रही थी तब 15-20 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया और ट्रैक्टर ले गए, इतना ही नहीं, पुलिस जवानों की जेब में जबरन पैसे रखकर वीडियो भी बनाया।**

'राष्ट्रपति चुनाव में ममता के सुझाये नाम का समर्थन करेगी सपा'

अयोध्या, 14 जून (वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो नाम तय करेंगी, उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

यादव ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस नाम का प्रस्ताव रखेंगी, समाजवादी पार्टी उसी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दस लाख नौकरी देने की बात कही है, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपना संकल्प पत्र तो देखे कि जिसमें 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। केन्द्र सरकार ने एलआईसी, बैंक, एयर लाइन, तेल कम्पनी समेत तमाम सरकारी कम्पनियां बेच दी हैं। अब रेलवे को बेचने की तैयारी है। जब ये सब सरकार बेंच दे रही है तो नौकरी सरकार कहां से देगी।

- **समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया ।**

सपा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ। सरकार ने कहा था कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है तो वह बतायें कि अगर अच्छा बजट है तो किसान, व्यापारी क्यों परेशान हैं। आज प्रदेश का हर आम नागरिक महंगाई से परेशान है।

जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके

श्रीनगर, 14 जून(वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में मंगलवार को मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गयी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी।

केन्द्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के बदख्शन प्रांत में 36.52 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.18 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था और भूकंप के झटके कुछ ही सेकेंड के लिए महसूस किए गए।

सेनाओं में 'भर्ती किये जायेंगे "अग्निवीर"

नई दिल्ली 14 जून (वार्ता)। सरकार ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए एक नयी योजना अग्निपथ के जरिये केवल चार वर्ष के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति में इस निर्णय को मंजूरी दी गयी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत ही जवानों यानी अग्निवीरों की भर्ती की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सेनाओं को चुस्त दुरूस्त, युवा तथा जोश और उत्साह से परिपूर्ण बनाना है। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगा, साथ ही इसके जरिये युवाओं को देश सेवा करने का मौका मिलेगा और उनमें देशप्रेम की भावना भी पैदा होगी।

- **सरकार ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए केवल चार वर्ष के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने का निर्णय लिया ।**

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को गौरवपूर्ण भविष्य तथा सशस्त्र बलों से जुड़कर राष्ट्रसेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी ने युवाओं को गौरवपूर्ण भविष्य व सशस्त्र बलों से जुड़ राष्ट्रसेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इससे उनमें क्षमताओं व कौशल का निर्माण होगा, साथ ही देश का रक्षातंत्र और सशक्त होगा। इस निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूँ। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक क्रांतिकारी पहल है।

विपक्ष के खेमे में एकता से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, इस प्रकार की स्थिति सदैव ही नेतृत्व प्रदान करती आई है।

वामदलों ने कहा है कि 15 जुलाई का दिन शरद पवार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष तथा वामदलों की बातचीत के लिये पहले ही निर्धारित हो चुका था।

वामपंथियों का तृणमूल कांग्रेस के प्रति, तथा खासतौर से ममता बनर्जी के प्रति मनमुटाव तथा वैमनस्य है तथ वे एक विपक्षी नेता के रूप में, उन (ममता) पर जरा भी भरोसा एवं विश्वास नहीं करते। ममता-शासित बंगाल में दोनों ही वामपंथी दलों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है तथा वे विरोध या आंदोलन करने की स्थिति में भी नहीं रहे हैं।

मूल बात यह है कि ममता बनर्जी के विरोध के लिये, विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार के मुद्दे पर अन्य सभी दलों पर बढ़त बनाने की हताशापूर्ण एवं अवांछित कोशिश कर रही हैं। जबकि, अपना दबदबा बनाने की खातिर, कांग्रेस से छिटक रहे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की उनकी भूमिका के चलते, ममता बनर्जी स्वयं ही एक संदिग्ध व्यक्तित्व बन गई हैं।

उन्हें अन्दर तक जानने वाले लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की खातिर, विपक्ष की एकता को नष्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि अभी हाल ही हुये चुनावों में, पश्चिम बंगाल के बाहर सीटें जीत पाने में रही उनकी घोर असफलता ने उनकी महत्वाकांक्षाओं का ध्वस्त कर दिया था।

लेकिन वे आसानी से मानने वाली भी नहीं हैं। ममता बनर्जी ने चुनिन्दा नेताओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर विचार-विमर्श शुरु कर दिया है। मंगलवार को, उन्होंने नैशनल कांग्रेस प्रमुख शरद पवार के साथ मीटिंग की थी। जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव के गणित का प्रश्न है, कुछ चीजें भाजपा के पक्ष में हैं, हालाँकि यह कहा जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिहाज से उनके पास कुछ वोट कम हैं। लेकिन ओडिशा के बीजू जनता दल तथा दक्षिण की कुछ अन्य पार्टियों की अपेक्षित सहानुभूति के बल पर, भाजपा इस चुनाव को आराम से जीत सकती है।

पिछले रिकॉर्डों तथा राज्य-स्तरीय गणित को देखा जाये, इस समय किसी भी पक्ष में जाने की स्थिति में बैठे लोग, कुछ उपादेय सौदेबाजी के फलस्वरूप, सत्तारूढ़ दल की ओर चले जायेंगे। राष्ट्रपति चुनाव बहुत तेजी से व्यावसायिक एवं लेन-देन का सौदा बनता जा रहा है। विपक्षी एकता थोथे शब्दों तक सीमित रह जायेगी।

- **इन दोनों नेताओं का यह भी मानना है कि, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण, यह बैठक बुलाना व विपक्ष का सर्वसम्मत उम्मीदवार तय करना, कांग्रेस की जिम्मेवारी है।**
- **इन वामपंथी नेताओं के अनुसार, कांग्रेस की अध्यक्ष व उनकी पार्टी के नेता इस संदर्भ में 15 तारीख को शरद पवार से वैसे भी मिल रहे हैं।**

सीजीएसटी के दो अधिकारी चार लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भरतपुर, 14 जून (निसं)। अलवर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर सीजीएसटी के दो अधिकारियों को भरतपुर एसीबी के एएसपी महेश मीणा की टीम ने ट्रेप कर ऑयल मिल के मालिक से ली 4 लाख की रिश्वत को जब्त कर गिरफ्तार किया । ये राशि अधिकारी धनराज अधीक्षक व विनय इंस्पेक्टर ने फर्जी स्टॉक बताकर ऑयल मिल के मालिक से मांगी थी।

एएसपी महेश मीणा ने बताया कि दोनों अधिकारी भरतपुर के रीको इंड्रस्टीज एरिया में एक ऑयल मिल पर फर्जी स्टॉक बताकर ऑयल मिल मालिक से 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे। 4 लाख में सौदा हुआ, ऑयल मिल के मालिक ने इसकी शिकायत की और उन्हें अलवर जाते समय गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार धनराज कुमावत सुपरिटेंडेंट, दूसरा आरोपी विनय यादव आज दोनों भरतपुर के रीको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक ऑयल मिल पर पहुंचे और ऑइल मिल का स्टॉक चेक किया। तब दोनों आरोपियों ने ऑयल मिल मालिक को बताया की उन्होंने 9 करोड़ का फर्जी स्टॉक कर रखा है। दोनों अधिकारियों ने ऑयल मिल मालिक को डरा धमका कर उससे 10 लाख की रिश्वत की मांग की।

- **सी.जी.एस.टी. के सुपरिन्टैन्डैंट धनराज कुमावत और इंस्पैक्टर विनय यादव ने रीको इण्डस्ट्रीज की एक ऑयल मिल के मालिक से डरा धमका कर 4 लाख रू. की रिश्वत ली।**
- **उन्होंने मिल में 9 करोड़ रू. का फर्जी स्टॉक होने का झूठा आरोप लगाया और दस लाख रू. मांगे, बाद में 4 लाख रू. में सौदा तय हुआ।**

शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अधिकारियों की गाड़ी को रीको के पम्प पर रोक लिया और उसे चेक किया तो गाड़ी में 4 लाख रुपये रखे हुए थे जिस पर दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी ने अपना नाम गोपनीय रखा है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908